

माननीय श्री एम. एम. कुमार और टी.पी.एस मान, न्यायमूर्ति  
सत्येन्द्र जीत सिंह-याचिकाकर्ता  
बनाम  
भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 10854/सीएटी 2003  
6 जनवरी 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद- 226—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'ए' नियम, 1987- संयुक्त पद पर पदोन्नति आयुक्त-याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्ति को नियमित पदोन्नति दी गई .याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद - डीपीसी लेने में विफल रही.

1989-90 के लिए याचिकाकर्ता के खाते की ग्रेडिंग 'बहुत अच्छी' के रूप में दर्ज की गई

प्राधिकरण की समीक्षा - उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा स्वीकृत यूपीएससी का दृष्टिकोण सही नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से लागू न होने से ग्रस्त है माना- कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन है और 16(1)-डीपीसी द्वारा विचार किया गया कि याचिकाकर्ता के पास 'अच्छी' रिपोर्ट थी 1989-90 जबकि वास्तव में यह (बहुत अच्छा) भौतिक रूप से प्रभाव डालेगा

परिणाम- ट्रिब्यूनल ने इसे अपनाकर खुद को गलत दिशा दी दृष्टिकोण-याचिका स्वीकार की गई, उत्तरदाताओं को समीक्षा बुलाने का निर्देश दिया गया . दो माह की अवधि में डीपीसी की बैठक।

माना गया कि याचिकाकर्ता अपनी एसीआर के रूप में बेंच मार्क को पूरा कर सकता है.

वर्ष 1987, 1988 और 1989 'बहुत अच्छे' हैं और वर्ष 1985 के संबंध में भी

पहली छमाही के लिए यह 'बहुत अच्छा' है जबकि वर्ष 1985 की दूसरी छमाही और 1986 का पूरा वर्ष इसे 'अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, यूपीएससी का दृष्टिकोण इस प्रकार है

25 अक्टूबर 2002 के अपने संचार में उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा स्वीकार किया गया,सही नहीं है क्योंकि इसमें दिमाग का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। इस तरह के एक कार्रवाई स्पष्ट रूप से संविधान अनुच्छेद 14 और 16(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमाना है

निश्चित रूप से, यदि 3 का बेंच मार्क 5 में से 'बहुत अच्छा' रिपोर्ट देता है मार्च, 1992 में डीपीसी द्वारा विचार-विमर्श के बाद रिपोर्टें स्थापित की गईं याचिकाकर्ता के पास वर्ष 1989-90 में एक 'अच्छी' रिपोर्ट थी जबकि यह वास्तव में थी.

'बहुत अच्छा\* परिणामों पर भौतिक प्रभाव डालेगा। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने किया है

उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाकर स्वयं को गलत दिशा दी।

(पैरा 16 एवं 17)

डी. एस. पटवालिया.अधिवक्ता/या याचिकाकर्ता।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील परवीन चंदर गोयल।

राजीव शर्मा, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

### निर्णय

माननीय एम. एम. कुमार, न्यायमूर्ति.

1. संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इन कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि "क्या संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'यूपीएससी') के लिए सरकार के अनुरोध को नजरअंदाज करना उचित है भारत में एक समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षिप्तता के लिए 'डीपीसी') बुलाने के लिए, खासकर जब यह याचिकाकर्ता के पक्ष में अतिरिक्त सामग्री पर आधारित हो, जिसे पहले पदोन्नति के लिए अयोग्य के रूप में खारिज कर दिया

गया था।" याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षिप्तता के लिए 'द ट्रिब्यूनल') की चंडीगढ़ बेंच द्वारा पारित दिनांक 07.04.2003 के आदेश को चुनौती देते हुए यह सवाल उठाया है, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया है।

2. पहले कुछ तथ्य सामने रखे जा सकते हैं ताकि विवाद को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके। याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 1980 में यूपीएससी द्वारा ली गई सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के बाद किया गया था। उन्हें सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ए' सेवा में सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें 1981 बैच के लिए आवंटित किया गया था। यह निर्विवाद है कि उनकी सेवा शर्तें वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'ए' नियम 1987 (संक्षेप में '1987 नियम') के रूप में जाना जाता है। सेवा के अधिकारियों के बीच कुछ आपसी वरिष्ठता विवाद था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। मुकदमे के लंबित होने के कारण, पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर कुछ तदर्थ पदोन्नति की गई। याचिकाकर्ता को तदर्थ आधार पर तदर्थ संयुक्त आयुक्त और फिर अतिरिक्त आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया था। मार्च, 2002 में संयुक्त आयुक्त पद पर नियमित पदोन्नति हेतु डीपीसी बुलाई गई। डीपीसी से पहले सफल होने वालों के संबंध में, दिनांक 03.05.2002 को एक अधिसूचना जारी की गई और तदर्थ बेसिक पर काम करने वाले कई अधिकारियों को नियमित आधार पर संयुक्त आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता का नाम अधिसूचना में जगह नहीं पाया, हालांकि श्री मोहिंदर सिंह जैसे उनसे कनिष्ठ व्यक्ति को नियमित पदोन्नति दी गई थी। अधिसूचना में घोषित किया गया कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए 'अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि वह विभिन्न सरकारी नीतियों और निर्देशों द्वारा निर्धारित बेंच मार्क 'बहुत अच्छा' हासिल करने में विफल रहा था।

3. याचिकाकर्ता ने 21.05.2002 (पी-6) को एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया और दावा किया कि किसी अधिकारी को पदोन्नति से वंचित करने के दो बुनियादी कारण हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पहला कारण सतर्कता मंजूरी का अभाव हो सकता है और दूसरा कारण बेंच मार्क तक पहुंचने में असमर्थता हो सकता है। पहले के संबंध में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 20 साल के अपने सेवा करियर के दौरान, उन्होंने एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि अर्जित नहीं की और उनके खिलाफ कभी भी कोई आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया या लंबित नहीं किया गया और पूरी अवधि के दौरान उनके

प्रदर्शन की सराहना की गई। उच्चतम स्तर पर. उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें 1985 और 1990 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अध्यक्ष की प्रशस्ति समिति द्वारा सम्मानित किया गया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने 1985 और 1990-91 की अवधि के दौरान गुजरात के बुहल, जामनगर और प्रोबंदर जैसे देश के दूरदराज के हिस्सों में सेवा की। और अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभाया, जिसे विधिवत रूप से चेयरमैन के प्रशस्ति प्रमाणपत्र से मान्यता मिली। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि सहायक कलेक्टर के रूप में उन्हें 5.50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। दूसरे कारण के संबंध में, याचिकाकर्ता ने बताया कि वर्ष 1990-91 के लिए, उस वर्ष की एसीआर में गलती से यह दर्शाया गया है कि वह ड्यूटी से अनुपस्थित थे, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं थे। इसके विपरीत, उन्होंने किसी भी अधिकारी के अधीन 90 दिनों से अधिक काम नहीं किया, जो एसीआर लिखने के लिए न्यूनतम निर्धारित अवधि है। उपरोक्त गलती को तब सुधारा गया जब समीक्षा डीपीसी द्वारा उपायुक्त के रूप में पदोन्नति के उनके मामले पर दोबारा विचार किया गया। उनकी वरिष्ठता भी पुनः तय की गई और उन्हें श्री मोहिंदर सिंह से वरिष्ठ स्थान दिया गया।

4. संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए नियमित डीपीसी के संबंध में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पराजय का मुख्य कारण वर्ष 1990-91 के लिए उनकी एसीआर है, जिसे पहले ही गैर-स्थायी घोषित किया जा चुका है और इसे नहीं किया जा सकता था। उनकी पदोन्नति को नियमित करने पर विचार किया गया। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्टिंग वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के लिए समीक्षा अधिकारी द्वारा उनका मूल्यांकन 'बहुत अच्छा' किया गया था और मार्च/अप्रैल 2002 में आयोजित डीपीसी के लिए बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' था। . याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 5 में से तीन 'बहुत अच्छी' रिपोर्ट का मानक हासिल कर लिया है क्योंकि उनके पास तीन से अधिक रिपोर्ट 'बहुत अच्छी' श्रेणी में थीं। उन्होंने आगे दावा किया है कि डीपीसी सेवा रिकॉर्ड के आधार पर और दिनांक 10.04.1989 के निर्देशों के आलोक में पदोन्नति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए बाध्य थी। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि चेयरमैन के प्रशस्ति प्रमाण पत्र, नकद पुरस्कार और उत्कृष्ट रिपोर्ट सहित उनका पूरा सेवा रिकॉर्ड डीपीसी के समक्ष नहीं रखा गया था।

5. याचिकाकर्ता द्वारा 21.05.2002 को दिए गए अभ्यावेदन पर भारत सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया। यूपीएससी को संबोधित पत्र दिनांक 05.06.2007 (पी-7) में, भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद पुनर्विचार की गुंजाइश है क्योंकि एसीआर के संबंध में उसकी ग्रेडिंग वर्ष 1987-88 और 1988-89 'बहुत अच्छे' हैं और उन्होंने यूपीएससी से उनके अभ्यावेदन की जांच करने और संयुक्त आयुक्त के पद पर उनकी तदर्थ पदोन्नति को नियमित करने के लिए समीक्षा डीपीसी के लिए अनुरोध करने का अनुरोध किया। यूपीएससी को भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाव में कोई सार नहीं मिला और निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था, जो डीपीसी के समक्ष रखे गए थे और इसलिए उसका पुनः निर्धारण करने के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित करने का कोई कारण नहीं था। संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता, यूपीएससी का उपरोक्त निर्णय भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को भेजे गए पत्र दिनांक 25.10.2002 में परिलक्षित हुआ है। परिणामस्वरूप आदेशों को ओए संख्या 1117/सीएच/2002 दायर करके ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे 07.04.2003 को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डीपीसी के पास उसे पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसके पास 3 से अधिक रिपोर्टों को 'बहुत अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके मूल आवेदन के पैरा 4 (xi) में दिए गए अनुरोध के अनुसार उनकी एसीआर निम्नलिखित तालिका में दी गई है, जो इस प्रकार हैं:

i) वर्ष 1985 वर्ष की पहली छमाही में बहुत अच्छा और दूसरी छमाही में 'अच्छा'।

ii) 1986 'अच्छा'

iii) 1987 'बहुत अच्छा'

iv) 1988-89 'बहुत अच्छा'

v) 1989-90 रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उन्हें अच्छा ग्रेड दिया गया था

जबकि समीक्षा प्राधिकारी ने कारण दर्ज करने के बाद उसे 'बहुत अच्छा' ग्रेड दिया।

6. याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा किया कि वर्ष 1989-90 के लिए उनकी रिपोर्ट को केवल 'अच्छा' माना गया जबकि यह वास्तव में 'बहुत अच्छा' है, ऐसा लगता है कि प्राधिकरण ने समीक्षा प्राधिकरण की रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया, जिसने

रिपोर्टिंग अधिकारी की रिपोर्ट को 'बहुत अच्छा' कर दिया। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया कि भारत सरकार के यूपीएससी के अनुरोध को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, खासकर जब एसीआर में भौतिक परिवर्तन हुआ हो, जिसके परिणामस्वरूप बेंच मार्क 'बहुत अच्छा' प्राप्त होगा। याचिकाकर्ता. उपरोक्त मुद्दे पर ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण पैरा 12 और 13 से स्पष्ट है। संक्षेप में, पैरा 12 में ट्रिब्यूनल को यह समझाने में परेशानी हो रही है कि यूपीएससी भारत सरकार की सनक और कल्पना और जारी किए गए निर्देश के अधीन नहीं है। भारत सरकार द्वारा यूपीएससी पर बाध्यकारी नहीं है। ट्रिब्यूनल ने हमारे संविधान के तहत 'स्पॉइल सिस्टम' के लिए कोई स्थान देने से इनकार करके संस्थापक पिता के मूल दर्शन का उल्लेख किया है और फिर पैरा 13 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है:

"13. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम आवेदक की ओर से इस अतिवादी निवेदन को अस्वीकार करना चाहेंगे कि नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सरकार के पास यूपीएससी को समीक्षा डीपीसी बुलाने की आवश्यकता के लिए पूर्ण शक्ति है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में, यूपीएससी को सरकार से निर्देश नहीं लेना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक रोजगार के मामले में सरकार का अंतिम अधिकार होता है। आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है और संविधान में विशेष रूप से अनुच्छेद में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है | 320 अपनी प्रक्रिया और इसके कामकाज को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार। निश्चित रूप से, कार्यकारी सरकार यूपीएससी को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं है।"

7. ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि भारत सरकार द्वारा यूपीएससी को समीक्षा डीपीसी बैठक बुलाने के लिए बाध्यकारी प्रकृति का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। वास्तव में अपने दिनांक 05.06.2002 के संचार में, भारत सरकार ने दिनांक 21.05.2002 (पी-6) के अभ्यावेदन की जांच करना यूपीएससी के पूर्ण विवेक पर छोड़ दिया है, जो याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया था और फिर तथ्यों पर निष्कर्ष निकाला गया था। रिकॉर्ड/दस्तावेज़ में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था, जिस पर पहले ही 07.03.2002/18.03.2002 को बुलाई गई डीपीसी द्वारा विचार किया जा चुका है। ट्रिब्यूनल ने दिनांक 10.04.1989 के निर्देशों के पैरा 18.1 के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले की भी जांच की और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

"जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समीक्षा डीपीसी आयोजित करने के लिए जिन स्थितियों पर विचार किया गया है, वे वहां आकर्षित होंगी जहां डीपीसी के समक्ष रखे गए भौतिक तथ्य सही नहीं थे या जहां ये भौतिक तथ्य बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव से बदल जाते हैं या जहां डीपीसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया थी। प्रासंगिक नियमों/निर्देशों का उल्लंघन। आवेदक का मामला उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक में नहीं आता है। उपरोक्त निर्देश बिना किसी वैध कारण के अधिकारियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित करने का प्रावधान नहीं करते हैं। कोई तकनीकी या तथ्यात्मक गलती नहीं स्थापित कर दिया गया है और आवेदक के सीआर डोजियर के आधार पर, उसकी ग्रेडिंग नहीं बदलेगी। एक समीक्षा डीपीसी केवल तभी आयोजित की जा सकती है जब गलती ऐसी हो जिसके परिणामस्वरूप आवेदक की बेहतर ग्रेडिंग हो और वह 'फिट' हो जाए। 'अयोग्य' के बजाय। मामले का सार यह है कि समीक्षा डीपीसी को केवल पूछने के लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है। समीक्षा डीपीसी के अनुरोध का समर्थन करने के लिए कुछ व्यापक और अस्पष्ट आरोप लगाकर डीपीसी द्वारा चयन को दबाया या गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यदि इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने की अनुमति दी जाती है तो उच्च निष्ठा और योग्यता वाले व्यक्तियों से बनी कितनी भी निष्पक्ष संस्था द्वारा किया गया हर चयन आलोचना का शिकार हो जाएगा। आवेदक का मामला समीक्षा डीपीसी बुलाने के लिए निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता है।"

8. ट्रिब्यूनल द्वारा विचार किया गया एक अन्य पहलू यह है कि वह डीपीसी द्वारा की गई सिफारिश पर अपील नहीं कर सकता है। उस संबंध में, ट्रिब्यूनल ने दलपत अब्बासदाहेब सोलंके बनाम डॉ. डीबी महाजन, एआईआर 1990 एससी 434, एमपी राज्य बनाम श्रीकांत चापेकर, 1992 (5) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया।) एसएलआर 635 और श्रीमती। नूतन अरविंद बनाम भारत संघ और अन्य, 1996(1) एसएलआर 774 और अन्य निर्णय।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री डीएस पटवालिया ने तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता की इस दलील को गलत तरीके से खारिज कर दिया है कि नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते सरकार के पास यूपीएससी को समीक्षा डीपीसी बुलाने की आवश्यकता की पूर्ण शक्ति है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यूपीएससी एक स्वतंत्र निकाय हो सकता है, लेकिन एक बार सरकार ने अपने संचार दिनांक 05.06.2002 (अनुलग्नक पी -7) में पाया है कि वर्ष 1989-90 के लिए याचिकाकर्ता की

रिपोर्ट को 'अच्छी' से अपग्रेड कर दिया गया था। 'बहुत अच्छा' तो एसीआर में बदलाव से डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। विद्वान वकील के अनुसार, दिनांक 07.03.2002/18.03.2002 को जब याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया तो डीपीसी के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड में वर्ष 1989-90 के लिए उसका एसीआर 'अच्छा' दिखाया गया था जैसा कि पढ़ने से स्पष्ट है। इस न्यायालय द्वारा 17.07.2008 और 24.07.2008 को पारित दो आदेश।

10. श्री पटवालिया ने आगे आग्रह किया है कि भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'ए' नियम, 1987 (संक्षिप्तता के लिए 'नियम') के रूप में जाना जाने वाला नियम, जो संयुक्त आयुक्त के पद पर याचिकाकर्ता की पदोन्नति को नियंत्रित करता है, स्पष्ट रूप से दिखाएं कि पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए डीपीसी में यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के दो सदस्य शामिल हैं। इसलिए, डीपीसी की संरचना ऐसी है कि यूपीएससी का 25% प्रतिनिधित्व है क्योंकि यूपीएससी से केवल एक सदस्य को डीपीसी बैठक की अध्यक्षता करनी है जबकि तीन सदस्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से आने हैं। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम टीवी पटेल (2007) 4 एससीसी 785 के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है और तर्क दिया है कि यूपीएससी द्वारा दी गई सलाह संविधान का अनुच्छेद 320(3) प्रकृति में सलाहकार/सिफारिशात्मक है और राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

11. श्री पटवालिया ने आगे तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश के पैरा 17 में इस निष्कर्ष पर पहुंचकर एक और गंभीर त्रुटि की है कि याचिकाकर्ता का मामला दिनांक 10.04.1989 के निर्देशों के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता है। समय-समय पर संशोधन किया जाता है। विद्वान वकील के अनुसार, प्रारंभिक पैरा 18.1 स्वयं याचिकाकर्ता के मामले को कवर करेगा और तथ्यों और परिस्थितियों में, समीक्षा डीपीसी बुलाने का आदेश दिया जाना चाहिए था। उन्होंने प्रारंभिक पैरा 18.1 का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि डीपीसी की कार्यवाही की समीक्षा की जा सकती है, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि भौतिक तथ्य डीपीसी के ध्यान में नहीं लाए गए हैं। विद्वान वकील के अनुसार, एक बार वर्ष 1989-90 से संबंधित एसीआर को समीक्षा प्राधिकारी द्वारा 'अच्छे' से 'बहुत अच्छा' में अपग्रेड कर दिया गया था, जिसे



07.03.1992/18.03.1992 को डीपीसी के समक्ष नहीं रखा गया था, तब वहां परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन है और कुछ तथ्य डीपीसी के ध्यान में नहीं लाए गए। डीपीसी ने वर्ष 1989-90 से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर ही याचिकाकर्ता के मामले की जांच की है कि यह 'अच्छा' था। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि दिनांक 10.04.1989 के निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, बिल्कुल गलत था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्देश केवल उदाहरणात्मक हैं और निर्देशों के अंत में संपूर्ण नहीं हैं, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिन कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे संपूर्ण नहीं थे बल्कि केवल उदाहरणात्मक थे।

12. भारत संघ के विद्वान वकील श्री परवीन चंद्र गोयल ने तर्क दिया है कि यूपीएससी की सलाह आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है जब तक कि इससे असहमत होने के अच्छे कारण न हों। विद्वान वकील के अनुसार, एक बार जब यूपीएससी ने समीक्षा डीपीसी न बुलाने के लिए अपनी राय व्यक्त कर दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, तो यह अदालत के लिए बाध्यकारी प्रकृति के निर्देश जारी करने के लिए खुला नहीं होगा। इसी तरह, यूपीएससी के विद्वान वकील श्री राजीव शर्मा ने तर्क दिया है कि एसीआर के अलावा, अन्य कारकों ने भी यूपीएससी द्वारा राय बनाने में अपनी भूमिका निभाई है जब डीपीसी 07.03.2002 और 18.03.2002 को आयोजित की गई थी। श्री शर्मा के अनुसार, केवल एसीआर ही संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का आधार नहीं है, बल्कि कई अन्य कारक भी हैं।

13. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हम इस आदेश के पहले पैराग्राफ में उठाए गए कानून के मूल प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मामला 17.07.2008 को विचार के लिए आया जब डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के मूल तर्क पर ध्यान दिया कि वर्ष 1989-90 के लिए, रिपोर्टिंग अधिकारी ने याचिकाकर्ता की एसीआर को 'अच्छा' दर्ज किया था और डीपीसी ने दर्ज एसीआर पर विचार किया था। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा डीपीसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए मार्च 1992 में हुई समीक्षा प्राधिकरण द्वारा उनकी ग्रेडिंग को 'अच्छी' से 'बहुत अच्छी' में बदल दिया गया था। डिवीजन बेंच ने उत्तरदाताओं को वर्ष 1992 में आयोजित डीपीसी से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का

निर्देश दिया। सुनवाई की अगली तारीख पर, रिकॉर्ड सीलबंद कवर के साथ पेश किया गया और यह पाया गया कि विद्वान वकील द्वारा उठाया गया विवाद सराहनीय था। 24.07.2008 को, डिवीजन बेंच ने एक आदेश पारित किया जो स्वतः स्पष्ट है और इस प्रकार है:

"यूपीएससी के उप सचिव श्री नरसिंग देव ने विभागीय पदोन्नति समिति का रिकॉर्ड पेश किया है, जिसकी पांच अलग-अलग तारीखों यानी 07.03.2002 और 18.03.2002 के बीच बैठक हुई और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया। संयुक्त आयुक्त। रिकार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 62 पर है और वर्ष 1989-90 के मुकाबले याचिकाकर्ता को अच्छा ग्रेड दिया गया है। श्री देव का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष रिपोर्टिंग अधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी का है। यूपीएससी द्वारा ग्रेडिंग के निर्धारण का आधार नहीं है। वास्तव में, यूपीएससी अधिकारी के एसीआर रिकॉर्ड में विभिन्न इनपुट के आधार पर एक अधिकारी को ग्रेड देता है। यह कहा गया है कि इस तरह की ग्रेडिंग जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में स्वीकार्य है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। वह ऐसे निर्देश तैयार करने के लिए कुछ समय चाहता है।"

14. सुनवाई के दौरान, यूपीएससी के विद्वान वकील श्री राजीव शर्मा कोई निर्देश प्रस्तुत नहीं कर पाए, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यूपीएससी को विभिन्न आधारों पर एक अधिकारी को ग्रेड देने की अनुमति देते हुए जारी किया गया हो। उनके एसीआर में इनपुट। तदनुसार, हम पाते हैं कि ऐसे किसी भी निर्देश के अभाव में समीक्षा प्राधिकारी द्वारा दी गई ग्रेडिंग को अंतिम माना जाना चाहिए। कुल परिणाम यह है कि वर्ष 1989-90 की एकमात्र गोपनीय रिपोर्ट को मार्च 1992 में आयोजित डीपीसी द्वारा 'अच्छा' माना गया था, जिसे वास्तव में रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा 'बहुत अच्छा' में अपग्रेड किया गया है। इस आधार पर ही रिव्यू डीपीसी बुलाने का मामला बनता है। यह समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी यह निष्कर्ष कैसे दर्ज कर सकता है कि डीपीसी के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड/दस्तावेजों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था और पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए डीपीसी बैठक की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं था। संयुक्त आयुक्त का पद निकाला गया। हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता का एक सराहनीय उद्देश्य यूपीएससी द्वारा पूरी तरह से दिमाग न लगाने से विफल हो गया है, इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार ने अपने दिनांक 05.06.2002 के पत्र में यूपीएससी को स्पष्ट रूप से

बताया है कि इसमें योग्यता थी। याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के लिए उनकी एसीआर ग्रेडिंग के रूप में दिया गया प्रतिनिधित्व 'बहुत अच्छा' है। हमारा यह भी विचार है कि भारत सरकार ने यूपीएससी के दृष्टिकोण को यांत्रिक रूप से स्वीकार करके कानून में गंभीर त्रुटि की है कि याचिकाकर्ता के मामले पर फिर से विचार करने के लिए समीक्षा डीपीसी बैठक का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

15. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाव की अस्वीकृति से संबंधित प्रश्न की जांच की जानी है। रिकॉर्ड के अवलोकन से, इस न्यायालय ने 24.07.2008 को अपने आदेश में पहले ही स्पष्ट रूप से दर्ज कर लिया है कि वर्ष 1989-90 के लिए, याचिकाकर्ता की 'बहुत अच्छी' ग्रेडिंग को ध्यान में नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि अगर 5 में से 3 रिपोर्ट को 'बहुत अच्छा' की श्रेणी में रखा जाता है और कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है तो वह 'बहुत अच्छा' के बेंच मार्क को पूरा कर लेंगे। उनकी एसीआर का विहंगम दृश्य नीचे दिया गया है:

i) वर्ष 1985 वर्ष की पहली छमाही में बहुत अच्छा और दूसरी छमाही में 'अच्छा'।

ii) 1986 'अच्छा'

iii) 1987 'बहुत अच्छा'

iv) 1988-89 'बहुत अच्छा'

v) 1989-90 रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उन्हें अच्छा ग्रेड दिया गया था

जबकि समीक्षा प्राधिकारी ने कारण दर्ज करने के बाद उसे 'बहुत अच्छा' ग्रेड दिया।

16. उपरोक्त बायोडाटा से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता बेंच मार्क को पूरा करेगा क्योंकि वर्ष 1987, 1988 और 1989 के लिए उनकी एसीआर 'बहुत अच्छी' है और वर्ष 1985 के संबंध में भी पहली छमाही के लिए यह 'बहुत अच्छी' है जबकि वर्ष 1985 की दूसरी छमाही और 1986 के पूरे वर्ष को 'अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, हम पाते हैं कि उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा दिनांक 25.10.2002 (पी-8) के संचार में स्वीकार किया गया यूपीएससी का दृष्टिकोण सही नहीं है क्योंकि यह दिमाग के पूर्ण गैर-प्रयोग से ग्रस्त है। ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

17. ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल ने दो मामलों में खुद को गलत दिशा दी है। सबसे पहले, ट्रिब्यूनल ने राय दी कि संस्थापक पिता द्वारा खारिज की गई लूट प्रणाली को यूपीएससी की सलाह को नजरअंदाज करके रास्ता नहीं खोजना चाहिए। उपरोक्त मुद्दा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से अप्रासंगिक है क्योंकि यहां एक उन्नत रिपोर्ट, जिसे पहले मार्च 1992 में आयोजित डीपीसी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, को समीक्षा डीपीसी के समक्ष रखने की मांग की गई थी। इसलिए, यह पूरी तरह से दिमाग न लगाने का नतीजा है कि याचिकाकर्ता जैसे अधिकारी के मामले को नुकसान हुआ है। इसी तरह, ट्रिब्यूनल इस मुद्दे पर लड़खड़ा गया कि उसे डीपीसी द्वारा आयोजित कार्यवाही पर अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करना था। यहां तक कि यह सवाल भी नहीं उठेगा क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम मार्च 1992 में आयोजित डीपीसी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की दोबारा जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा गया था, जो महत्वपूर्ण हो सकती है डीपीसी द्वारा की गई अनुशंसा के परिणाम पर प्रभाव। निश्चित रूप से, यदि 5 रिपोर्टों में से 3 'बहुत अच्छी' रिपोर्टों का बेंच मार्क स्थापित किया गया है तो मार्च 1992 में डीपीसी द्वारा विचार किया जाएगा कि याचिकाकर्ता के पास वर्ष 1989-90 में एक 'अच्छी' रिपोर्ट थी जबकि वास्तव में यह 'अच्छी' रिपोर्ट थी। बहुत अच्छा परिणामों पर भौतिक प्रभाव डालेगा। इसलिए, हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाकर खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है।

18. हमारा यह भी मानना है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में दम है जब उन्होंने तर्क दिया कि दिनांक 10.04.1989 के निर्देश वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित थे। निर्देशों के पहले पैराग्राफ से ही पता चल जाएगा कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समीक्षा डीपीसी का मामला बनता है। उपरोक्त दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए, निर्देशों को पढ़ना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं:

"18.1 किसी भी डीपीसी की कार्यवाही की समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब डीपीसी ने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार नहीं किया है या यदि डीपीसी के ध्यान में भौतिक तथ्य नहीं लाए गए हैं या डीपीसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां हुई हैं इस प्रकार, कुछ अनजाने गलतियों को सुधारने के लिए समीक्षा डीपीसी बुलाना आवश्यक हो सकता है जैसे:

क) जहां पात्र व्यक्तियों पर विचार नहीं किया गया

; या

बी) जहां

गलती से अयोग्य व्यक्तियों पर विचार किया गया था; या

ग) जहां किसी व्यक्ति की वरिष्ठता को संशोधित किया जाता है

पूर्वव्यापी प्रभाव के परिणामस्वरूप डीपीसी के समक्ष रखी गई वरिष्ठता सूची में भिन्नता आ गई; या

घ) जहां डीपीसी द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितता की गई हो; या

ई) जहां डीपीसी द्वारा अधिकारी के मामले पर विचार करने के बाद सीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों को कम कर दिया गया या हटा दिया गया।

ये उदाहरण संपूर्ण नहीं हैं बल्कि केवल उदाहरणात्मक हैं।"

शुरुआती पैरा 18.1 को पढ़ने से पता चलेगा कि किसी भी डीपीसी की कार्यवाही की समीक्षा की जानी चाहिए यदि डीपीसी ने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है या भौतिक तथ्यों को डीपीसी के ध्यान में नहीं लाया गया है या प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि है। इसके बाद, खण्ड (ई) में यह विचार किया गया है कि यदि गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियाँ डीपीसी के बाद हटा दी जाती हैं तो समीक्षा डीपीसी का मामला बनाया जाएगा।

19. वर्तमान मामले में, मार्च 1992 में आयोजित डीपीसी, वर्ष 1989-90 के संबंध में समीक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज की गई याचिकाकर्ता से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करने में विफल रही, जिसने 'बहुत अच्छा' अपग्रेड किया, जबकि डीपीसी के समक्ष रखी गई सामग्री उसे केवल 'अच्छा' दिखाया। यहां तक कि याचिकाकर्ता को नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र देने वाले अन्य रिकॉर्ड भी डीपीसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि दिनांक 10.04.1989 के निर्देशों के तहत भी,

याचिकाकर्ता उस तारीख से संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए अपने मामले पर पुनर्विचार करने के लिए समीक्षा डीपीसी बैठक का हकदार हो गया है, जब वह उससे कनिष्ठ था। श्री मोहिंदर सिंह पर विचार किया गया और उन्हें पदोन्नत किया गया।

20. उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, यह याचिका सफल होती है। आदेश दिनांक 25.10.2002 (पी-8) निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल का दिनांक 07.04.2003 का आदेश (पी-12) भी रद्द किया जाता है। शुरुआती पैरा में उठाए गए कानून के सवाल का जवाब यूपीएससी और सरकार के खिलाफ दिया गया है। तदनुसार, उत्तरदाताओं को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर समीक्षा डीपीसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 को यूपीएससी के समक्ष याचिकाकर्ता से संबंधित सही रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उसका एसीआर, प्रशस्ति प्रमाण पत्र और याचिकाकर्ता को दिए गए अन्य सभी पुरस्कार शामिल होने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस बार कोई त्रुटि नहीं हुई है। यदि याचिकाकर्ता मेधावी पाया जाता है तो उसे उस तारीख से संयुक्त आयुक्त के रूप में पदोन्नति दी जानी चाहिए, जिस दिन मोहिंदर सिंह जैसे उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता को उसकी लागत का हकदार माना जाता है, जो ₹25,000/- निर्धारित है। लागत का भुगतान याचिकाकर्ता को दो महीने के भीतर उसके नाम पर डिमांड ड्राफ्ट जारी करके किया जाएगा।

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

**हरिकिशन**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**गुरुग्राम, हरियाणा**